खास-खबरें

आयकर रिटर्न दाखिल करने में सिर्फ छह दिन बाकी, अंतिम तिथि 31 जुलाई

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख बेहद नजदीक है। वित्त वर्ष 2025-26 (आंकलन वर्ष 2026-27) के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय है। आईटीआर फाइल करने के लिए अब सिर्फ छह दिन ही बचे हैं। आयकर विभाग ने शनिवार को एक्स पोस्ट में कहा कि आखिरी समय का इंतजार न करें, आकलन वर्ष 2026-27 के लिए अपना आईटीआर-1 और आईटीआर-2, 31 जुलाई, 2026 से पहले फाइल करें। विभाग ने कहा कि http://incometax.gov.in पर जाकर अपना आयकर रिटर्न बिना किसी जुर्माने के दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से पहले दाखिल करें। आयकर विभाग ने कहा कि अधिकांश वेतनभोगी और व्यक्तिगत करदाताओं को 31 जुलाई की अंतिम तिथि और समय से बचने के लिए आधिकारिक इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना रिटर्न जरूर दाखिल कर लेना चाहिए। अगर आप 31 जुलाई की अंतिम समय-सीमा को चूक जाते हैं, तो आपके पास बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का विकल्प रहता है।

महानदी अपतटीय क्षेत्र में पहले मूल्यांकन कुएं की खुदाई शुरू

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को महानदी अपतटीय बेसिन में पहले मूल्यांकन कुएं की ड्रिलिंग शुरू करने की घोषणा की है। पुरी ने इसको ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में अहम कदम बताया है। हरदीप सिंह पुरी ने इस अवसर को 'ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में भारत की यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत' बताया। उन्होंने कहा कि ड्रिलिंग की शुरुआत एक दशक के दूरदर्शी सुधारों का परिणाम है। मंत्री ने कहा कि इन सुधारों ने देश के अन्वेषण और उत्पादन परिदृश्य को बदल दिया है।

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने सरकार के अन्वेषण सुधारों के तहत हुई प्रगति के बारे में बताते हुए बताया कि ओएएलपी के तहत लगभग 3.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 172 अन्वेषण ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, जिनमें 4.3 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया गया है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ही लगभग 674 कुओं की खुदाई की गई, पांच नए भंडार खोजे गए और सात भंडारों से उत्पादन शुरू हुआ। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हर एक मीटर की ड्रिलिंग हमें आयात पर निर्भरता कम करने, आत्मनिर्भरता मजबूत करने और विकसित भारत के सपने को साकार करने के करीब लाती है। उन्होंने इसके लिए ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय, तकनीकी भागीदारों और संपूर्ण अन्वेषण समुदाय को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि आज शुरू हुई खुदाई भारत के अपतटीय अन्वेषण प्रयासों को और मजबूत करेगी और देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य में योगदान देगी।

विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह को निर्यात-आयात के लिए मिली मंजूरी, 18 अगस्त से शुरू होगा परिचालन

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली/तिरुवनंतपुरम। केरल स्थित विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह को विदेशों के साथ सामान का आयात और निर्यात शुरू करने के लिए सीमा शुल्क विभाग की मंजूरी मिल गई है। विझिंजम इंटरनेशनल सी-पोर्ट लिमिटेड (वीआईएसएल) ने शनिवार को एक बयान में कहा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने इसको शुरू करने की मंजूरी दे दी है। बंदरगाह को 18 अगस्त से निर्यात और आयात कार्गो परिचालन शुरू करने की अंतिम मंजूरी दी गई है। सीबीआईसी के 24 जुलाई को जारी आदेश के मुताबिक तिरुवनंतपुरम के पास स्थित विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह अब तक केवल अंतरराष्ट्रीय पारवहन केंद्र के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन 18 अगस्त 2026 से यहां माल के निर्यात और आयात का परिचालन भी शुरू हो जाएगा।

वीआईएसएल के मुताबिक वर्तमान में बंदरगाह से संबद्ध कोई निर्धारित कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) नहीं होने के कारण सीबीआईसी ने निर्यात और आयात कार्गो के प्रबंधन के लिए कई शर्तें निर्धारित की हैं। कंटेनर फ्रेट स्टेशन बंदरगाह के पास स्थित एक ऐसा केंद्र होता है, जहां आयात और निर्यात होने वाले कंटेनरों में रखे सामान की जांच, पैकिंग, खोलने, दोबारा भरने और सीमा शुल्क से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी स्पेसएक्स को सफलता

स्टारशिप की 13वीं परीक्षण उड़ान सफल 20 उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित

हिंद महासागर में नियंत्रित जल अवतरण, चंद्र और मंगल अभियानों की तैयारी को मिली नई गति

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी स्पेसएक्स ने अपने विशालकाय स्टारशिप रॉकेट की 13वीं परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी करते हुए 20 नए स्टारलिंक उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए। मिशन के निर्धारित चरण पूरे करने के बाद रॉकेट के ऊपरी भाग ने हिंद महासागर में नियंत्रित जल अवतरण किया। इस परीक्षण को कंपनी के अब तक के सबसे सफल अभियानों में से एक माना जा रहा है।

स्टारशिप ने अमेरिका के टेक्सास स्थित प्रक्षेपण केंद्र से उड़ान भरी। उड़ान के दौरान रॉकेट ने सफलतापूर्वक चरण पृथक्करण की प्रक्रिया पूरी की और इसके बाद 20 नए संस्करण के स्टारलिंक उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए। ये उपग्रह परीक्षण के उद्देश्य से प्रक्षेपित किए गए थे। मिशन का प्रमुख उद्देश्य नई तकनीकों का परीक्षण, उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली की जांच तथा भविष्य के चंद्र और मंगल अभियानों की तैयारी को आगे बढ़ाना था।

मिशन के दौरान रॉकेट के ऊपरी भाग ने अंतरिक्ष में निर्धारित सभी प्रमुख परीक्षण पूरे किए। पुनः पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के बाद उसने नियंत्रित ढंग से हिंद महासागर में जल अवतरण किया। कंपनी के अनुसार इस बार ऊष्मा सुरक्षा कवच का प्रदर्शन पहले की तुलना में बेहतर रहा और यान अपेक्षाकृत सुरक्षित अवस्था में समुद्र तक पहुंचा। इससे पुनः उपयोग योग्य रॉकेट विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी प्राप्त हुई।

हालांकि रॉकेट का प्रथम चरण निर्धारित योजना के अनुरूप पूरी तरह सफल नहीं हो सका। वापसी के दौरान सभी आवश्यक इंजन पुनः प्रारंभ नहीं हो पाए, जिसके कारण उसका नियंत्रित अवतरण नहीं हो सका और वह अपेक्षा से अधिक वेग के साथ समुद्र में गिरा। इसके बावजूद मिशन से प्राप्त आंकड़ों को भविष्य के अभियानों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यह परीक्षण कंपनी की पुनः उपयोग योग्य अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली विकसित करने की योजना का महत्वपूर्ण चरण है। इसी प्रौद्योगिकी के आधार पर भविष्य में चंद्रमा और मंगल के लिए मानव तथा सामग्री भेजने की तैयारी की जा रही है। साथ ही स्टारलिंक उपग्रह समूह के विस्तार की दिशा में भी इस मिशन को महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

'वील्स ऑफ इंडिया' महोत्सव में 116 विरासत बुनाई शैलियों के हस्तनिर्मित वस्त्र प्रदर्शित

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: राजधानी के जनपथ स्थित केंद्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम में शुक्रवार को 'वील्स ऑफ इंडिया' महोत्सव का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के अधीन विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय की ओर से आयोजित यह महोत्सव 24 जुलाई से 7 अगस्त तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। इसका आयोजन 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है।

कपड़ा मंत्रालय के अनुसार यह महोत्सव भारत की समृद्ध और विविध हथकरघा परंपराओं को एक मंच पर प्रस्तुत कर रहा है। प्रदर्शनी में देशभर की 116 विरासत हथकरघा बुनाई शैलियों के उत्कृष्ट हस्तनिर्मित वस्त्र प्रदर्शित किए गए हैं। इसके माध्यम से आगंतुक भारतीय बुनकरों की पीढ़ियों से चली आ रही कारीगरी, कलात्मक उत्कृष्टता और सांस्कृतिक विरासत को निकट से देख और समझ सकेंगे।

प्रदर्शनी में ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मणिपुर, छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना, गुजरात, जम्मू-कश्मीर और त्रिपुरा सहित अनेक राज्यों की प्रसिद्ध बुनाई परंपराओं को स्थान दिया गया है। इसमें बनारसी, जामदानी, कांचीपुरम रेशम, संबलपुरी इकत, पैठणी, कानी पश्मीना, बावन बूटी, कोटपाड, इलकल, कासरगोड, हिमरू तथा रिशा जैसी विशिष्ट बुनाई शैलियां प्रदर्शित की गई हैं। ये सभी अपने-अपने क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान और वस्त्र परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं।

महोत्सव का उद्देश्य प्रामाणिक हस्तनिर्मित हथकरघा उत्पादों के प्रति लोगों में जागरूकता और सम्मान बढ़ाना है। साथ ही यह सतत, नैतिक और कारीगर आधारित उत्पादन प्रणाली के महत्व को भी रेखांकित करता है। यह आयोजन बुनकरों, अभिकल्पकारों, संग्रहकर्ताओं, खरीदारों, शोधकर्ताओं और आम नागरिकों के बीच संवाद तथा विचार-विमर्श का महत्वपूर्ण मंच भी उपलब्ध करा रहा है।

सप्ताहभर में सोना-चांदी की कीमतों में उछाल

सोना 2,622 रुपये और चांदी 7,247 रुपये महंगी, निवेशकों की बढ़ी रुचि

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सोना और चांदी की कीमतों में इस सप्ताह उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारतीय सर्राफा एवं आभूषण व्यापार संघ के अनुसार 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत 2,622 रुपये बढ़कर 1.44 लाख रुपये पर पहुंच गई है। पिछले सप्ताह 18 जुलाई को इसकी कीमत 1.41 लाख रुपये थी। वहीं चांदी की कीमत में भी 7,247 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई, जिसके बाद इसका भाव 2.15 लाख रुपये से बढ़कर 2.23 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गया।

वर्ष 2026 के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। इस वर्ष अब तक सोना लगभग 11 हजार रुपये महंगा हो चुका है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोने का भाव 1.33 लाख रुपये से अधिक था, जो अब बढ़कर 1.44 लाख रुपये पर पहुंच गया है। दूसरी ओर चांदी की कीमत में वर्ष की शुरुआत की तुलना में लगभग 7 हजार रुपये की कमी बनी हुई है। 31 दिसंबर 2025 को चांदी 2.30 लाख रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो वर्तमान में 2.23 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है। इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख रुपये और चांदी ने 3.86 लाख रुपये प्रति किलोग्राम का सर्वकालिक उच्च स्तर भी छुआ था।

वस्तु बाजार विशेषज्ञ अजय केडिया के अनुसार सोना और चांदी अपने उच्चतम स्तर से काफी नीचे आ चुके हैं। ऐसे में निवेशक इनमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन एकमुश्त निवेश से बचना चाहिए। उनका मानना है कि वर्ष के अंत तक सोना 1.60 लाख रुपये और चांदी 2.80 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है।

विशेषज्ञों ने आभूषण खरीदते समय केवल भारतीय मानक ब्यूरो की मुहर वाले प्रमाणित सोने की खरीद करने की सलाह दी है। साथ ही खरीदारी से पहले सोने का वजन और उस दिन का बाजार भाव अवश्य जांचना चाहिए। चांदी की शुद्धता की पहचान के लिए चुंबक परीक्षण, बर्फ परीक्षण, गंध परीक्षण और सफेद कपड़े से रगड़कर जांच करने जैसे सरल उपाय भी उपयोगी बताए गए हैं।

होंडा की नई प्रमुख एसयूवी भारत में लॉन्च किया

22.8 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज, आठ वायु सुरक्षा कुशन और संकर तकनीक से लैस

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: होंडा कार्स इंडिया ने अपनी नई प्रमुख एसयूवी जेडआर-वी को भारतीय बाजार में पेश कर दिया है। कंपनी ने इसे 47.99 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर उतारा है। यह वाहन जापान से पूर्ण रूप से निर्मित इकाई के रूप में आयात किया गया है और फिलहाल केवल एक पूर्ण सुविधायुक्त संस्करण में उपलब्ध होगा। नई जेडआर-वी में दो लीटर क्षमता का संकर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो दो विद्युत मोटरों के साथ कार्य करता है। यह संयोजन 184 अश्वशक्ति और 315 न्यूटन मीटर बल उत्पन्न करता है। कंपनी का दावा है कि यह वाहन 22.8 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है। यह शून्य से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति 7.9 सेकंड में प्राप्त कर सकता है, जबकि इसकी अधिकतम गति 171 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुरक्षा के लिहाज से वाहन में आठ वायु सुरक्षा कुशन, चालक सहायता प्रणाली, 360 डिग्री कैमरा, टायर दबाव निगरानी प्रणाली तथा अन्य उन्नत सुरक्षा सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा इसमें नौ इंच का स्पर्श आधारित सूचना एवं मनोरंजन तंत्र, 10.25 इंच का डिजिटल उपकरण पटल, द्वि-क्षेत्रीय स्वचालित तापमान नियंत्रण, 12 स्पीकर वाला ध्वनि तंत्र, बिना तार की मोबाइल चार्जिंग, विद्युत चालित पिछला दरवाजा और परिवेश प्रकाश व्यवस्था जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। वाहन का बाहरी स्वरूप आकर्षक और आधुनिक बनाया गया है। इसमें पूर्ण प्रकाश उत्सर्जक डायोड आधारित हेडलैंप, 18 इंच के मिश्रधातु पहिए, छत पर पीछे की ओर वायु पंख तथा आकर्षक पिछली प्रकाश व्यवस्था दी गई है। यह चार रंगों में उपलब्ध होगी। भारतीय बाजार में जेडआर-वी का मुकाबला प्रीमियम श्रेणी की कई उपयोगी खेल वाहन श्रेणी की गाड़ियों से होगा। कंपनी का उद्देश्य संकर तकनीक, बेहतर ईंधन दक्षता, उन्नत सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से इस श्रेणी के ग्राहकों को नया विकल्प उपलब्ध कराना है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों को नकली 'एयर सुविधा 2.0' वेबसाइटों को लेकर दी चेतावनी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को फर्जी 'एयर सुविधा 2.0' पोर्टलों से सतर्क रहने की चेतावनी दी है, जो उन यात्रियों को पेमेंट गेटवे पर भेजकर ठगी कर रहे हैं।

मंत्रालय ने ये स्पष्ट किया है कि स्व-घोषणा फॉर्म भरना पूरी तरह निःशुल्क है। ऐसे में आधिकारिक पोर्टल 'एयर सुविधा 2.0' का ही उपयोग करें।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को जारी बयान में बताया कि यात्रियों को नकली 'एयर सुविधा 2.0' वेबसाइटों से सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि उन फर्जी वेबसाइटों और पोर्टल्स के बारे में ये चेतावनी जारी की गई, जो खुद को आधिकारिक 'एयर सुविधा 2.0' प्लेटफॉर्म बताते हैं और यूजर्स को पेमेंट गेटवे पर भेजते हैं।

मंत्रालय ने बताया कि 'एयर सुविधा 2.0' की सेवाएं मुफ्त हैं और यात्रियों को 'सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म' (स्व-घोषणा पत्र) जमा करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होता है।

नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि संज्ञान में आया है कि कुछ फर्जी वेबसाइटें और पोर्टल एयर सुविधा 2.0 होने का ढोंग कर रहे हैं और यात्रियों को भुगतान गेटवे पर पुनर्निर्देशित करके उन्हें गुमराह कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि एयर सुविधा 2.0 का एकमात्र आधिकारिक पोर्टल https://airsuvidha.civilaviation.gov.in/ है। ऐसे में यात्रियों से आग्रह किया जाता है कि वे किसी भी व्यक्तिगत या यात्रा संबंधी जानकारी साझा करने से पहले वेबसाइट यूआरएल की ध्यानपूर्वक जांच कर ले और एयर सुविधा 2.0 सेवाएं प्रदान करने का दावा करने वाली किसी भी अनधिकृत वेबसाइट पर भुगतान करने से बचें।

मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों को सूचित किया जाता है कि एयर सुविधा 2.0 सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं और स्व-घोषणा पत्र जमा करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे केवल आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करें और प्रामाणिक जानकारी के लिए सरकारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

8.25 प्रतिशत की दर से राशि जमा, चार तरीकों से की जा सकती है शेष राशि की जांच

भविष्य निधि खातों में ब्याज जमा होना शुरू

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि खातों में 8.25 प्रतिशत की दर से ब्याज जमा करना शुरू कर दिया है। अनेक खाताधारकों को ब्याज की राशि जमा होने के संदेश भी मिलने लगे हैं। जिन खाताधारकों को अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्याज जमा करने की प्रक्रिया अभी जारी है।

खाताधारक संदेश का इंतजार करने के बजाय संगठन द्वारा उपलब्ध कराए गए आधिकारिक माध्यमों से अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते की शेष राशि की जांच कर सकते हैं। इसके लिए छूटी हुई कॉल, लघु संदेश सेवा तथा अन्य अधिकृत माध्यमों सहित कुल चार तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। इससे यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वित्त वर्ष 2025-26 का ब्याज खाते में जमा हुआ है या नहीं।

इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने राशि निकासी के नियमों में भी बदलाव किया है। नए प्रावधानों के अनुसार अब कोई भी सदस्य अपने पात्र शेष धन की पूरी राशि आंशिक निकासी के रूप में नहीं निकाल सकेगा। प्रत्येक सदस्य को अपने पात्र शेष धन का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि खाते में बनाए रखना होगा। यदि किसी सदस्य के खाते में पात्र शेष धन एक लाख रुपये है, तो उसे 25 हजार रुपये खाते में रखना अनिवार्य होगा। ऐसे में केवल शेष 75 हजार रुपये ही निकाले जा सकेंगे।

संगठन जल्द ही एक नई व्यवस्था के तहत स्वचालित धन निकासी मशीन और एकीकृत भुगतान प्रणाली के माध्यम से भी कर्मचारी भविष्य निधि की राशि निकालने की सुविधा शुरू करने की तैयारी में है। इस पहल के लागू होने के बाद लगभग 7.8 करोड़ सदस्यों को बिना कागजी प्रक्रिया के शीघ्र धनराशि उपलब्ध कराई जा सकेगी।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित प्रक्रियाएं अधिक सरल और सुविधाजनक होंगी। इसमें स्वचालित दावे के निपटान तथा सदस्य की पसंद के बैंक खाते में सीधे धनराशि हस्तांतरित करने जैसी सुविधाएं भी शामिल रहेंगी।

स्पेशल खबर 55 प्रतिशत निर्यात पर ही लागू होगा 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क, सरकार ने दी जानकारी

अमेरिकी टैरिफ से भारत के 45 प्रतिशत निर्यात को राहत

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कहा है कि अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर घोषित 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क का प्रभाव देश के सभी निर्यात पर नहीं पड़ेगा। सरकार के अनुसार अमेरिका को होने वाले भारत के लगभग 45 प्रतिशत निर्यात इस अतिरिक्त शुल्क के दायरे से बाहर रहेंगे, जबकि शेष 55 प्रतिशत निर्यात पर यह शुल्क लागू होगा।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ने 23 जुलाई को अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974 के तहत भारत सहित 60 अर्थव्यवस्थाओं के विरुद्ध अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी। यह शुल्क उन उत्पादों के आयात को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से लगाया गया है, जिनके निर्माण में बेगार का उपयोग होने की आशंका जताई गई है।

मंत्रालय के अनुसार अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान में किसी अतिरिक्त शुल्क के दायरे में नहीं आता। इसमें सामान्य उपयोग की औषधियां, स्मार्टफोन तथा कुछ अन्य अधिसूचित उत्पाद शामिल हैं। ये सभी उत्पाद नए 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क से भी मुक्त रहेंगे। इसके अलावा अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 232 के अंतर्गत पहले से शामिल इस्पात, एल्यूमिनियम तथा वाहन पुर्जों जैसे उत्पादों पर भी यह अतिरिक्त शुल्क लागू नहीं होगा।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि धारा 232 के अंतर्गत लगाए गए शुल्क सीमित अपवादों को छोड़कर लगभग सभी देशों पर समान रूप से लागू होते हैं। इसी कारण इन उत्पादों को नए अतिरिक्त शुल्क से अलग रखा गया है। सरकार का अनुमान है कि इन छूटों के कारण भारत के लगभग 45 प्रतिशत निर्यात पर नए शुल्क का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि शेष 55 प्रतिशत निर्यात पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लागू होगा।

सरकार ने यह भी कहा कि जांच के दायरे में आए अधिकांश अन्य देशों की तुलना में भारत पर इस शुल्क का प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहेगा। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने इस वर्ष दो जून को भारतीय उत्पादों पर 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद भारत सरकार ने विस्तृत लिखित प्रस्तुतियां, आमने-सामने परामर्श तथा सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेकर लगातार अपना पक्ष रखा। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत को अंतिम निर्णय में अतिरिक्त शुल्क की निचली श्रेणी में रखा गया, जिससे भारतीय निर्यात को प्रमुख क्षेत्रों में तुलनात्मक लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है।

मंत्रालय ने बताया कि दो फरवरी की घोषणा और सात फरवरी को जारी संयुक्त वक्तव्य के अनुरूप भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए दोनों देश मिलकर कार्य कर रहे हैं।

होंडा ने पेश किए 10 नए दोपहिया वाहन

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने भारतीय बाजार के लिए एक साथ 10 नए दोपहिया वाहनों का अनावरण किया है। कंपनी ने सात नए मॉडल और तीन अद्यतन संस्करण प्रस्तुत किए हैं। इन सभी मॉडलों को चरणबद्ध तरीके से बाजार में उतारा जाएगा। कंपनी का उद्देश्य प्रीमियम श्रेणी में अपनी उपस्थिति मजबूत करना और ग्राहकों को अधिक विकल्प उपलब्ध कराना है।

नई श्रृंखला में साहसिक स्कूटर, क्रूजर मोटरसाइकिल, साहसिक मार्गों के लिए तैयार मोटरसाइकिल, विद्युत दोपहिया वाहन तथा लचीले ईंधन तकनीक वाले मॉडल शामिल हैं। प्रमुख मॉडलों में एडीवी 160, एक्सआर 300 एल, एक्सआर 300 रैली, रिबेल 300, रिबेल 500, सीबी 500 तथा क्यूसी 3 शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी ने अपनी लोकप्रिय सीबी 350 श्रृंखला के अद्यतन संस्करण भी प्रदर्शित किए हैं।

कंपनी के अनुसार अधिकांश नए मॉडल भारत में ही निर्मित किए जाएंगे। इससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलने के साथ निर्यात की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। नए उत्पादों के माध्यम से कंपनी साहसिक यात्रा, लंबी दूरी की सवारी, शहरी उपयोग और विद्युत गतिशीलता जैसे विभिन्न वर्गों के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास कर रही है।

होंडा ने फिलहाल सभी मॉडलों की कीमतों और बिक्री शुरू होने की तिथियों की घोषणा नहीं की है। कंपनी ने बताया कि इनकी विस्तृत जानकारी चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी।